

राम मंदिर

प्राण प्रतिष्ठा काउंटडाउन
02 दिन शेषFLORENCE
Group of Institutions
(A Unit of Haji Abdul Razzaque Educational Society)
Irba, Ranchi-83319, Jharkhand

न्यूज रील्स

पीएम आवास
योजना कार्यक्रममें भावुक हुए मोदी
सोलापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
शक्तिवाहन को महाराष्ट्र के सोलापुर
में अटल अभियान (अमृत 2.0)
के तहत 1201 करोड़ रुपये की
सात प्रतियोजनों को भूमि-पूजन
किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास
योजना के तहत कुछ लागत को घर
की चाढ़ी भी संपूर्ण पीएम इस
दौरान भावुक हो गये। उन्होंने कहा
कि क्षेत्र मुझे भी बचपन में ऐसे
घर में रहने का कूमि मिला होता।
वह भाषण देते-देते कुछ देके
लिए खामोश रहा।राहुल गांधी ने ब्रह्मपुत्र
में बोट से सफर कियामाजुली। कांग्रेस की भारत जड़ो
व्यापार का शक्तिवाहन के लिए बोट
में बैठे। वे दुनिया के सबसे
बड़े द्वीप माजुली पहुँचे। यहाँ
कांग्रेस नेता जयशंकर शर्मा ने कहा
कि असम के मुख्यमंत्री बोतलाये
हुए, भारत जड़ो व्यापार को
कोई नहीं रोक सकता। हमने कोई
नियम नहीं तोड़ा।लालू और तेजस्वी
को इडी का समनपट्टना इडी ने रेलवे में जमीन के
बदले नौकरी देने के मामले में
मनी लाइंगा बंधनी पूछताछ के
लिए राजद नेता लालू प्रधान और
उनके देंते विधार के इडी सीएम
तेजस्वी यादव की समन
जारी किया है। लालू को 29 और
तेजस्वी को 30 जनवरी को
पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
इडी की टीम शक्तिवाहन को राहीं
आवास पहुँची। एक अधिकारी की
ओर समन दिया गया।हेमंत सरकार के चार साल: ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कदम
अबुआ आवास के लिए 31 लाख आवेदन, 29.97 लाख का सत्यापन

रामलला की पहली तस्वीर सामने आयी

आजाद सिपाही संवाददाता



धनबाद में कोयला कारोबारियों पर आयकर छापा का तीसरा दिन

300 करोड़ के अवैध निवेश के सबूत मिले

तीन करोड़ से अधिक
नकद पहले ही गिल घुका
विभाग टैक्स घोरी के
आकलन में गुटा

आजाद सिपाही संवाददाता

धनबाद। धनबाद में कोयला
कारोबारियों के वहाँ आयकर ने
वुद्धिवाहन को भागेमारी की थी।
आयकर की कार्रवाई तीसरे दिन
शक्तिवाहन को भी जारी रही। आयकर
को टीम ने कोयला कारोबारीअनिल गोयल और दीपक पोद्दार के
कई टिकानों पर शक्तिवाहन को भी
कागजातों को खांगालना जारी रखा।
सूत्रों के मुताबिक टीम को 300
करोड़ के अवैध निवेश के पुछाला
सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें 200
करोड़ दीपक पोद्दार और 100
करोड़ अनिल गोयल ने किया है।
टीम को भागेमारी के दौरान पहले
ही तीन करोड़ रुपये नकदी मिल
चुके हैं। साथ ही 18 से 20 करोड़
रुपये के जेरोट भी मिले हैं। इसके
अलावा कई बैंक लॉकर की भीजानकारी मिली है। सूत्रों के
मुताबिक आयकर की टीम ने अब
तक दोनों कारोबारियों के एक
सूत्रों के मुताबिक टीम को पुछाला
सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें 200
करोड़ दीपक पोद्दार और 100
करोड़ अनिल गोयल ने किया है।
टीम को भागेमारी के दौरान पहले
ही तीन करोड़ रुपये नकदी मिल
चुके हैं। साथ ही 18 से 20 करोड़
रुपये के जेरोट भी मिले हैं। इसके
अलावा कई बैंक लॉकर की भी

इडी के खिलाफ सड़कों पर उतरे आदिवासी संगठन

ठोल-नगाड़ों के साथ दिया
राजभवन के समक्ष धरना

- मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई से नाराज हैं आदिवासी संगठन
- सरना समिति के अध्यक्ष बोले, यहाँ तीर धनुष छल सकते हैं

आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को
प्रवर्वन निवेशलय (इडी) द्वारा
समन बार-बार भेजने के खिलाफ झारखंड के कई
आदिवासी शक्तिवाहन को सड़कों पर उतरे। केंद्रीय सरना
समिति के अध्यक्ष अंजय तिर्की
के नेतृत्व में मोरहावादी में
प्रदर्शनकारी जुटे।इसके बाद सभी ने पारंपरिक
झोल-नगाड़ के साथ राजभवन
की ओर कूच किया और वहाँ
धरना की। आदिवासी संगठनों
में मुख्यमंत्री को इडी द्वारा
लगातार समन भेजे जाने से
नाराजगी है। उन्होंने इडी पर केंद्र
सरकार के इशारे पर काम करने
का आरोप लगाया है।प्रदर्शनकारियों का कहना था
कि जानवृत्त कर राज्य सरकार
को परेशान किया जा रहा है। जो
सरकार जनकों के लिए काम कर
रही है, उसे गिराने की सजिश
की जारी रही है। इस द्वारा साजिश
का पुरोजार विरोध करेंगे।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि
शनिवार को जब सीएम हेमंत
सोरेन से इडी पूछताछ करेगी,
तब भी वे सीएम आवास के पास
जुटेंगे। केंद्रीय सरना समिति के
अध्यक्ष अंजय तिर्की ने कहा कि
पूरी तैयारी है। हम लोग

मुख्यमंत्री से आज होगी पूछताछ

रांची (आजाद सिपाही)। मुख्यमंत्री ने इडी को पूछताछ के
लिए 20 जनवरी का समय दिया है। इडी के सात समन के
बाद आठवें समन (पत्र) पर उन्होंने अपने आवास में
पूछताछ करने के लिए इडी अधिकारियों को बुलाया है। सूत्रों
के मुताबिक इडी के अधिकारी शनिवार को दोपहर 12 बजे
सीएम आवास पहुँचेंगे। उधर, प्रदर्शन के विध्यालय नहीं
जिंदगी इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की कर रही है। इडी इस
संबंध में मुख्य सचिव और डीजीटी को पहले ही पत्र लिख
करूँगी। मुख्यमंत्री आवास और इडी ऑफिस के कार्यालय
की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी है।साहिबगंज डीसी नहीं
पहुँचे इडी कार्यालयरांची (आजाद सिपाही)। साहिबगंज डीसी
सामाजिक साधारण को इडी ने शक्तिवाहन को
पूछताछ के लिए बुलाया था। वह इडी कार्यालय
नहीं पहुँचे। इडी ने 3 जनवरी को छापेमारी के
बाद उन्हें 17 जनवरी को समन भेजा गया था।
उनसे साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपये के अवैध
खनन मामले में पूछताछ होनी है। इसके
मुताबिक इडी उन्हें सख्त दियायत के साथ एक
बार किर समन भेजने की तैयारी में है।Deals in :
All types of CP Bath fitting,
Pumps, Sanitaryware,
Pipes & fitting

YASH ENTERPRISES

J.J. Road, Beside, Deepak Trading, Upper Bazar, Ranchi-01
Ratan Prasad
Mob. : 9835901322, 9709082614

कार्यशैली: सरकारी कर्मी की गिरफ्तारी का आदेश दबा रखी है पुलिस

न्याय की आस में बैठी है आदिवासी महिला

अनुसंधानकर्ता ने मामले को दबा रखा है

प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी का आदेश होने पर भी कांड के
अनुसंधानकर्ता एसआइ दीपक सिंह ने उसे अपने पास दबा रखा है।
इस संबंध में बूँदे डीएसपी निस्टापर केरोली ने बताया कि मामले के
सत्यापन होने के बाद बूँदे पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया
है। अब तक यह गिरफ्तारी नहीं किया गया। इसकी जानकारी नहीं है। बूँदे
वनेदार संस्कृत कुमार से इस संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि
अनुसंधानकर्ता बूँदे थाना के एसआइ दीपक सिंह है। दीपक सिंह से जब इस
वारे में 'आजाद सिपाही' संवाददाता ने पूछा कि आरोपी को क्यों गिरफ्तार
नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने उपरी साध ली।घुसकर गलीगलौंग किया। जाति
सूचक शब्दों के साथ अपमान किया गया। इतना ही नहीं छेड़खानी
भी की। ये तथाम बातें एकांग आदेश हैं। पुलिस मामले को दबा रखने के
एक बातें बातें एकांग आदेश हैं। लेकिन पुलिस मामले को दबा रखने के
दो बातें बातें एकांग आदेश हैं। तो उन्होंने बताया कि अनुसंधानकर्ता बूँदे
थाना के एसआइ दीपक सिंह है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है।एसटीएससी थाना में दर्ज है
मामला: आरोपी के खिलाफ एसपी
स्ट्रीट के बैंक लॉकर के द्वारा
खेंडिट पैसेस्टेट प्रखंड मैनेजर
(एजीएम) के पद पर कार्रवाई है।
वह सोनाहात के साथ गिरफ्तार
करने के प्रभार में है। खेंडिट को गिरफ्तार
करने का आदेश है। बूँदे पुलिस
उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है।एसटीएससी थाना में दर्ज है
मामला: आरोपी के खिलाफ एसपीस्ट्रीट के बैंक लॉकर के द्वारा
खेंडिट पैसेस्टेट प्रखंड मैनेजर

के पद पर कार्रवाई है। वह सोनाहात

के साथ गिरफ्तार करने के प्रभार में है।

खेंडिट को गिरफ्तार करने का आदेश है।

बूँदे प

संपादकीय

बच्चों की शिक्षा में बड़ी चुनौती

दे शे के ग्रामीण हिस्सों में स्कूली बच्चों की शिक्षा की स्थिति पर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एपीईआर) का ताजा संस्करण पहली नवर में जरूर चिंतित करता है, लेकिन समग्रता में देखने पर साधा हो जाता है कि हालात निराशाजनक नहीं, बल्कि चुनौतीपूर्ण है। 14 से 18 साल के आधे से ज्यादा बच्चे अगर तीसरी-चौथी क्लास के मैथ के संपूर्ण डिविजन प्रॉब्लम साल्व न कर सकें, तो वह काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। वहाँ यह है कि डिविजन करने की क्षमता को व्यावहारिक जीवन में काम आने वाली बुनियादी गणनाओं के लिए जरूरी माना जाता है। खास काम यह कि इन स्कूल-डिलास का एक बड़ा विस्तार मार्केट से कुछ ही कदम दूर है, लेकिन इस तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता कि इस उम्मीद सहूल के लोगों को रिपोर्ट में पिछली बार 2017 में कवर किया गया था और इस दौरान देश-दुनिया ने कोरोना महामारी की जबर्दस्त चुनौती झेली है। खास कर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई तो कोरोना काल में लगवाया थप ही हो गयी थी।

महामारी के संदर्भ में रिपोर्ट की दो बातें खास तौर पर ध्यान खींचती हैं। एक तो यह कि 89 फोसदी बच्चे ऐसे हैं, जिनके घर में स्पार्ट फोन है। बहाँ, 92 फोसदी बच्चों ने बातात्वा के लिए स्पार्ट फोन ले लिए।

पुनौती बड़ी इसलिए भी है कि स्कूली पढ़ाई की नियमित प्रक्रिया में इस्के पाठ्यक्रमों के दौरान अनेक बच्चों के टेक्स्ट बुक को पाली करते हैं। उनके लिए बच्चों की बुनियादी समझ पर ध्यान देना मुश्किल होता है।

चलाना जानते हैं। निश्चित रूप से इसके पाठ्यक्रमों के दौरान अनेक बच्चों की भजबूरी का बड़ा हाथ माना जा सकता है। दूसरी बात यह कि एसरोलमेंट की संस्था (86.8 फोसदी) का 2017 (85.6 फोसदी) से ज्यादा होना बताता है कि महामारी के दौरान अजीविका के नुकसान के चलते ज्यादातर बच्चों के दोबारा स्कूल न लौटने का डर गलत साबित हआ है। हालांकि इसी रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि कीबैक एक तिहाई बच्चों 12वें से अगे नहीं पहुंचते। लड़कों के मामले में ड्रांप आउट की सबसे बड़ी वजह रुचि की कमी और गयी, तो लड़कियों के मामले में पारिवारिक मजबूरी। नियमित रूप से डेमोग्राफिक डिविडेंड पर ध्यान केंद्रित किये एक युवा देश के लिए यह चिंता की बात है। मैथश की बात हो या लैंगेज की, पढ़ाई में रिप्लायन अपने देश के लिए कोई नयी बात नहीं। एनुअल आर की ही पिछली रिपोर्टों में यह बात रेखांकित की जाती रही है, लेकिन यह कोई बचाव नहीं हो सकता। चुनौती बड़ी इसलिए भी है कि स्कूली पढ़ाई की नियमित प्रक्रिया में इसका इलाज नहीं है, क्योंकि बड़ी क्षमता में आकर्षणीय चालों के टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। उनके लिए बच्चों की बुनियादी समझ पर ध्यान देना मुश्किल होता है। जाहिर है, विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनॉमी बनने की राह पर बढ़ रहा देश इस चुनौती से मुंह नहीं मोड़ सकता।

अभिमत आजाद सिपाही

देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातियों के हित में सोचा और अलग से जनजातीय मंत्रालय का गठन किया। उस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी से आगे बढ़ावा दिया गया। जनजातीय समाज को सज्जनैतिक एवं सामाजिक ढंग से सशक्त करना यदि किंचित् मायाने में कोई कर पाया है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय नहीं जा सकता कि इस उम्मीद सहूल के लोगों को रिपोर्ट में पिछली बार 2017 में कवर किया गया था और इस दौरान देश-दुनिया ने कोरोना महामारी की जबर्दस्त चुनौती झेली है। खास कर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई तो कोरोना काल में लगवाया थप ही हो गयी थी।

पीएम जनमन: कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए एक आशा की किरण

अर्जुन मुंदा

जनजातीय समाजकरण, गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वित्त दशक के कार्यकाल में जो उपस्थिति हासिल की है, वे अतुलनीय हैं। आजादी के बाद सरकारों तो बदलती थी पर उनके एजेंट में अनुसूचित जनजातीय समाज दूर दूर तक कहाँ नजर नहीं आता था। देश अगे बढ़ता गया और जनजातीय समाज वहीं का वहीं रह गया। मूलभूत सुविधाओं की कमी और राजनैतिक उपेक्षाओं के कारण जनजातीय समाज मुख्यधारा से दूर रह गया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समूहों के हित में सोचा और अलग से जनजातीय मंत्रालय का गठन किया। उस काम को प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी से आगे ले गये। जनजातीय समाज को राजनैतिक एवं सामाजिक ढंग से सशक्त करना यदि किंचित् मायाने में कोई कर पाया है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिंतन हमेशा

ऐसी योजनाओं को धरातल पर लाने का होता है। जिनका मूलभूत उद्देश्य पिछड़े और अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को न्याय, समानता और सार्वभूतिक अधिकार देना होता है।

पीवीटीजी समुदाय अवसर वन क्षेत्रों के

सुदूर और दुम्प वर्सियों में रहते हैं।

पीएम जन मन अधियान को आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारें पहले आकड़ों को जोड़ने का काम करती थी लेकिन मैं आंकड़ों को नहीं, बल्कि जिंदी को जोड़ना चाहता हूँ। यह प्रधानमंत्री की जनजातीय समुदायों के प्रति संवेदनशीलता को चिनाता है।

प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण देते हुए भारत मंडपम, दिल्ली में पीएम जनमन के

कार्यालय न्याय, समाज अधियान (पीएम जनमन)

का शुभारंभ किया। यह एक ऐसी परियोजना है।

जिसकी कमी ने कल्पना भी

नहीं की थी।

हमारी सरकार ने देश के 18 राज्यों

और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 23 हजार से ज्यादा गांवों में रह रहे ऐसे 75 विशेष रूप से कर्मजोर जनजातीय व्यापारी के जनजातीय अधियान को आरंभ करते हुए 25 दिसंबर से देश के जनजातीय बाहुल्य जिलों में पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचने के उद्देश्य से, सूचना, शिक्षा और संचार (आइटी) अधियान की शुरुआत की है।

पिछले तीन सप्ताह में मंत्रालय द्वारा

100 से अधिक जिलों में 8000 से अधिक

कैप्ट लगाये गये, जिनमें आवश्यक

दस्तावेज़ जैसे अधिकारी विवरण

के लिए लगाये गये हैं।

ताकि जिलों के उद्योगों के

विवरण के लिए लगाये गये हैं।

पीएम जन मन के इस महामारी के अन्य

परिवर्तनों के साथ संस्थान के

सदस्यों ने श्रमदान कर

रामलला के आगमन पर पूरे

भारतवर्ष में उत्ताह का वातावरण

है। 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के

बाद प्रभु श्रीराम अपने भव्य महल

में विराजमान हो गये। उन्होंने कहा,

मंदिर हमारे गैरवबोध के

केंद्रीय चालों के

स्वच्छता के लिए जारी किया।

प्रधानमंत्री की जनजातीय समूहों के

विवरण की जिम्मेदारी

के लिए एक अद्वितीय

प्रयोग करने का आवश्यक

कार्यक्रम होता है।

प्रधानमंत्री की जनजातीय समूहों के

विवरण की जिम्मेदारी

के लिए एक अद्वितीय

प्रयोग करने का आवश्यक

कार्यक्रम होता है।

प्रधानमंत्री की जनजातीय समूहों के

विवरण की जिम्मेदारी

के लिए एक अद्वितीय

प्रयोग करने का आवश्यक

कार्यक्रम होता है।

प्रधानमंत्री की जनजातीय समूहों के

विवरण की जिम्मेदारी

के लिए एक अद्वितीय

प्रयोग करने का आवश्यक

कार्यक्रम होता है।

प्रधानमंत्री की जनजातीय समूहों के

विवरण की जिम्मेदारी

के लिए एक अद्वितीय

